



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, बुधस्पर्तिवार, जुलाई 30, 2009/श्रावण 8, 1931

No. 253]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2009/SRAVANA 8, 1931

खान मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2009

सं 27/79/2009-खान-II/एच पी सी.—भारत सरकार ने दिनांक 7 जनवरी, 2008 के संकल्प संख्या 11(39)/2007-खान-I के तहत, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने तथा संगठन और प्रौद्योगिकी तथा जनशक्ति संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उभरते हुए चुनौतियों का सामना करने में इसकी क्षमता का आंकलन करने के लिए, एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था।

2. एच पी सी ने 31 मार्च, 2009 का प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में प्रशिक्षण तथा क्षमता गठन के मुद्दों सहित कई सिफारिशों की हैं और कहा है कि प्रशिक्षण सेवाएं, विशेषकर भूविज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं :

- नए शामिल किए गए भूवैज्ञानिकों की दक्षता बढ़ाने के लिए शैक्षिक ज्ञान तथा फील्ड व्यवहार के मध्य अंतर को दूर करना।
- उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए प्रैक्टिसिंग भूवैज्ञानिकों को उनकी विशेषज्ञता से सम्बद्ध क्षेत्रों में नए परिवर्द्धनों से रूबरू कराकर ज्ञान वृद्धि करना।
- साहचर्यता बनाने के लिए सम्बद्ध क्षेत्रों के मध्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वार्ता करके ज्ञान की पूर्ति करना।
- दल भावना का सृजन करने के लिए अभिवृत्तिक मुद्दों, सहयोगात्मक व्यवहार, लक्ष्य अभिमुखीकरण, गुणवत्ता चेतना आदि से सम्बद्ध मानव संसाधन विकास।

3. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में भी आर एण्ड डी तथा प्रशिक्षण के लिए व्यापक सांस्थानिक ढांचे की आवश्यकता पर निम्नवत जोर दिया गया है :

“अत्याधुनिक गवेषण तकनीकों का उपयोग करने के लिए वैज्ञानिक खनन तथा अयस्क ड्रैसिंग तथा सज्जीकरण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खनिजों का इष्टतम उपयोग जरूरी है। साथ ही साथ खनिज उद्योग की जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास के लिए उपयुक्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण सुविधाओं को भी स्थापित करना जरूरी है। इन मुद्दों को परम महत्व दिया जाएगा और आर एण्ड डी तथा प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक सांस्थानिक रूपरेखा का विकास किया जाएगा। (एन एम पी 2008 का पैरा 2.7)

4. वर्तमान में जी एस आई तथा दूसरे संस्थाओं की प्रशिक्षण की जरूरत को कुछ हद तक 1976 में स्थापित भारतीय भूवैज्ञानिक प्रशिक्षण संस्थान (जी एस आई टी आई) द्वारा पूरा किया जाता है। जी एस आई टी आई का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद में है जिसमें फोटो भूविज्ञान तथा दूर संवेदी (जी जी आर एस), भूभौतिकी तथा भूआसूचना प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र (सी जी एम टी) जैसे विशिष्ट प्रभाग हैं। संस्थान के छः क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं जो स्थानीय भूविज्ञान के संबंध में विशिष्टता प्राप्त हैं। इन केंद्रों को केवल जी एस आई के नए भर्ती किए गए भूविदों को प्रवेश प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ काम में लाया जाता है। प्रशिक्षण सेवा आयोजना के समन्वयन के लिए महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की अध्यक्षता में एक प्रशिक्षण सलाहकार समिति है।

5. उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने मत व्यक्त किया है कि प्रशिक्षण संस्थान का मौजूदा ढांचा, यद्यपि सीमित संख्या (वर्ष में लगभग 50) में उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण देने और एक समय में 20-25 प्रशिक्षुओं के लिए कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण देने के मुख्य कार्य को पूरा करता है, कम क्षमता में उपलब्धता के मद्देनजर स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है।

6. एच पी सी ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षण आधारभूत संरचना में इसकी रिपोर्ट में कार्यक्रमात्मक सिफारिशों से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विशेषकर निम्न के लिए आमूलचूल सुधार की आवश्यकता है।

- प्रशिक्षण आधारभूत संरचना प्रतिवर्ष 300 तक नए भूवैज्ञानिकों के लिए 9-12 महीने का प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम हो।
- प्रशिक्षण आधारभूत संरचना जी एस आई तथा राज्य के सेवारत भूवैज्ञानिकों के लिए पुनश्चर्या अथवा कैपसूल पाठ्यक्रम प्रदान करने में भी सक्षम हो।
- इसमें हाई-इंड, कटिंग-एज ज्ञान प्रदान करने के लिए, विशेषकर जी एस आई तथा दूसरे केंद्रीय संस्थाओं के लिए क्षमता उपलब्ध होनी चाहिए।
- इसमें निजी क्षेत्र तथा दूसरे देशों के भूवैज्ञानिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिष्ठित सुविधा के तौर पर कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए।

7. एच पी सी ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षण को मिशन के तरीके से आरंभ किया जाए। हैदराबाद स्थित जी एस आई टी आई में प्रशिक्षण मिशन होगा और यह समग्र प्रशिक्षण नीति और समन्वयन और कार्यक्रम लक्ष्यों के लिए जिम्मेदार होगा। जी एस आई टी आई को उच्च गुणवत्ता कटिंग एज प्रशिक्षण/ज्ञान प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाए। जी एस आई टी आई हैदराबाद आदि स्थित विश्वविद्यालयों के साथ उपयुक्त व्यवस्था करके डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान बनने की आकांक्षा करेगा और तदनुसार एक नीति तैयार करे तथा क्षेत्रीय संस्थानों को एमएससी तथा पी एच डी के विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट मुद्दों पर उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए तदनुसूची सक्षमता का विकास करने की जरूरत है। इन्हें विशिष्ट फील्ड कार्यकलापों जैसे नमूना संग्रहण तथा ग्राउंड-टूथिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सम्पूरित किया जाएगा और ऐसे प्रशिक्षण के लिए विकल्प देने वाले विद्यार्थियों को नेशनल भूरासायनिक मानचित्रण, भूआकृतिक मानचित्रण अथवा हाइपरस्पेक्ट्रल मानचित्रण फील्ड कार्य के लिए एक भूवैज्ञानिक के साथ जमीनी कार्य में लगाया जाए। एच पी सी ने निम्नलिखित सिफारिशें भी की हैं।

- जी एस आई और राज्य डी जी एम के इंडेक्शन तथा सेवा प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक क्षेत्र को क्षेत्रीय संस्थान खोला जाए। क्षेत्रों में अवस्थित तथा जी एस आई टी आई की रिपोर्ट करने वाले निदेशक (प्रशिक्षण) को क्षेत्रीय संस्थान का प्रधान घोषित किया जाए और उसे समुचित प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाएं।
- क्षेत्रीय संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय परिसरों के भाग होंगे और क्षेत्रीय एच ओ डी के दिन-प्रतिदिन के नियंत्रण में कार्य करेंगे। निदेशक (प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय के भाग होंगे लेकिन क्षेत्रीय संस्थान में जी एस आई टी आई कार्यक्रमों के संचालन के लिए जी एस आई टी आई के कार्यात्मक प्रभार के अंतर्गत होगा।
- क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र बेहतर प्रबंधन नियंत्रण के उद्देश्य से जी एस आई टी आई की अपेक्षा क्षेत्रीय संस्थान के अधीन कार्य करेंगे। जैसा कि प्रत्येक एफ टी सी का एक विशिष्ट कार्य (क्षेत्रीय भूविज्ञान पर निर्भर) होता है, प्रत्येक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान को उसकी क्षेत्रीय उपस्थिति और सुसज्जित प्रयोगशालाओं से युक्त और क्षेत्र की विशिष्ट भूवैज्ञानिकों के आधार पर विशेषज्ञताओं की श्रेणी विकसित करना चाहिए।
- महानिदेशक, जी एस आई की अध्यक्षता वाली प्रशिक्षण सलाहकार समिति समय-समय पर विशिष्ट विषयों के लिए अतिरिक्त फील्ड प्रशिक्षण केंद्रों का सृजन करने की सिफारिश कर सकती है।

- जी एस आई टी आई जी एस आई के भूवैज्ञानिकों के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और क्षेत्रीय संस्थानों और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षक पाठ्यक्रम तथा विशिष्ट पाठ्यक्रमों का आयोजन करेगा और इस प्रयोजनार्थ, उपर्युक्त क्षेत्रीय विशिष्टीकरण की सीमा तक क्षेत्रीय संस्थान के संसाधनों का उपयोग करेगा।
- क्षेत्रीय संस्थान क्षेत्रीय जी एस आई भूवैज्ञानिकों, राज्य सरकार के भूवैज्ञानिकों के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम (सामान्यतया एक सप्ताह या कम) तथा क्षेत्रीय विशिष्टीकरण पर पाठ्यक्रमों का आयोजन करेगा।
- जी एस आई टी आई द्वारा राज्यों के डी जी एम की आवश्यकताओं को भी शामिल करते हुए अपने कार्यक्रमों और क्षेत्रीय कार्यक्रमों, दोनों के लिए प्रशिक्षण मिशन हेतु वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर को अपनी प्रशिक्षण सलाहकार समिति में अंतिम रूप दिया जाएगा और इसे अंतिम अनुमोदन के लिए सी जी पी बी के समक्ष रखा जाएगा।
- क्षेत्रीय संस्थान का कैलेण्डर राज्य के भूवैज्ञानिकों की आवश्यकताओं, क्षेत्रीय प्रशिक्षण आवश्यकता के आकलन और जी एस आई टी आई के सामान्य निदेशों को ध्यान में रखते हुए एस जी पी बी की इनपुट्स के आधार पर तैयार किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्रीय संस्थान को विशेष रूप से अपने क्षेत्र की राज्य सरकार के भूवैज्ञानिकों की आवश्यकताओं के अनुसार वर्ष में कम से कम एक पाठ्यक्रम आयोजित करना चाहिए और इसके क्षेत्रीय विशिष्टीकरण संबंधी पाठ्यक्रम, राज्य के भूवैज्ञानिकों के लिए भी खुले होने चाहिए ताकि वे भी विशेष रूप से क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों पर कुछ हद तक सामानांतर क्षमताएं विकसित कर सकें।
- प्रत्येक क्षेत्रीय संस्थान को अपने क्षेत्र में स्थित अथवा अपने क्षेत्र से संबंधित विशिष्टीकरण रखने वाले केंद्र और राज्य के भूवैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क बढ़ाना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण सेवाएं पेश करनी चाहिए। इसी प्रकार, क्षेत्रीय संस्थान को ऐसे संस्थानों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में मदद करने के लिए इनमें उपायकुशल व्यक्तियों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। वे संस्थान जो सी जी पी बी और इसकी समितियों का भाग हैं, वे स्पष्ट रूप से इस संबंध में पहले उम्मीदवार हैं।
- क्षेत्रीय संस्थान तकनीकी और प्रयोगशाला उपकरणों, विशेष रूप से, प्राप्त किए गए परिष्कृत उपकरणों की संभाल अथवा उपयोग करने वाले तकनीशियों और भूवैज्ञानिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं।

8. एच पी सी ने यह भी सिफारिश की है कि फिलहाल महानिदेशक की अध्यक्षता वाली 'प्रशिक्षण सलाहकार समिति' जिसमें क्षेत्रों और स्कंधों के प्रमुख शामिल हैं, को समिति द्वारा संस्तुत प्रशिक्षण सेवाओं के प्रति नए दृष्टिकोण को विकसित, कार्यान्वित और मॉनीटर करने के लिए ऊर्जित करने की आवश्यकता है। इस तथ्य को देखते हुए कि सभी स्टेकधारक संगठनों को कवर करने लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का व्यापक विस्तार किया जा रहा है, समिति सिफारिश करती है कि प्रशिक्षण सलाहकार समिति के अतिरिक्त सचिव, खान की अध्यक्षता में प्रशिक्षण नीति समन्वय समिति (टी पी सी सी) भी होनी चाहिए और टी पी सी सी समग्र नीति और वार्षिक रणनीति के लिए उत्तरदायी होगी।

9. सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उच्चाधिकार-प्राप्त समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और एतद्वारा यह संकल्प करती है कि प्रशिक्षण मिशन को हैदराबाद स्थित मौजूदा जी एस आई टी आई में स्थान दिया जाएगा और मौजूदा फील्ड प्रशिक्षण केंद्रों (एफ टी सी) को उन क्षेत्रों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा जिन क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में वे स्थित हैं। एफटीसी और जीएसआईटीआई के वर्तमान समूह ग एवं घ के पदधारी वरिष्ठता और पदोन्नति के उद्देश्यों से, ऐसी अवधि के लिए जो आवश्यक हो, वर्तमान केंद्रीकृत संवर्ग के भाग बने रहेंगे और इस प्रयोजन के लिए जीएसआईटीआई संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी होगा। एफटीसी के सभी पद, क्षेत्रीय कार्यालय के बजट में रहेंगे, जिनमें वे संबद्ध हैं और एफटीसी से संबंधित सभी परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक मामलों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय जिम्मेदार होंगे।

10. सरकार एतद्वारा एक प्रशिक्षण नीति समन्वय समिति (टीपीसीसी) का भी निम्नानुसार गठन करती है :

● सचिव, (खान) भारत सरकार	अध्यक्ष
● अपर सचिव/संयुक्त सचिव, (खान)	सदस्य
● संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (खान)	सदस्य
● महानिदेशक, जी एस आई	सदस्य
● अपर महानिदेशक, जीएसआई # (सपोर्ट सिस्टम-III) (विज्ञान नीति)	सदस्य
● उप महानिदेशक, जीएसआईटीआई	सदस्य सचिव
● विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि*	सदस्य
● भूविज्ञान मंत्रालय के प्रतिनिधि *	सदस्य
● मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि *	सदस्य
● कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय के प्रतिनिधि *	सदस्य

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिनिधि सदस्य
- दो राज्य सरकारों के खनन एवं भूविज्ञान, सचिव सदस्य
(जिन्हें प्रत्येक वर्ष नामित किया जाना है)

* संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं

प्रशिक्षण प्रबंधक के रूप में पदनामित

11. प्रशिक्षण मिशन की प्रशिक्षण गतिविधियों की समीक्षा, नीति अनुमोदन और रणनीतिक पहलों के लिए टीपीसीसी वर्ष में एक बार बैठक करेगी। टीपीसीसी सामान्यतया निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत कार्य करेगी :-

- बुनियादी दृष्टिकोण 'प्रशिक्षण सभी के लिए' होना चाहिए।
- प्रशिक्षण आवश्यकता का आकलन होना चाहिए और प्रशिक्षण आवश्यकताएं, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक इन हाऊस प्रशिक्षण के साथ-साथ बाहर से (अर्थात् जीएसआईटीआई के बाहर) प्रशिक्षण को कवर करते हुए, तय की जानी चाहिए।
- प्रशिक्षण को लक्षित समूह की प्रमुखता देते हुए भूवैज्ञानिक विषयों और प्रशासन/प्रबंधन क्षेत्रों दोनों को कवर करना चाहिए।
- प्रत्याशित उच्चतर दायित्वों के निर्वहन में समर्थ बनाने के लिए विभिन्न पदानुक्रम स्तरों पर आवधिक सेवाकालीन प्रशिक्षण की अवधारणा हो।
- प्रशिक्षण मिशन अपने मध्यम एवं उच्च प्रबंधनों हेतु शुल्क प्रदत्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एससीआई एवं आईआईएम जैसे संस्थानों की पहचान कर उनके साथ दीर्घकालिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- नए नियुक्तों के लिए परीवीक्षा के दौरान प्रशिक्षण के पश्चात एक विभागीय परीक्षा हो, जो परीवीक्षा की अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा होनी चाहिए।
- सपोर्ट स्ट्रीम स्टाफ को अपनी स्ट्रीम से संबंधित कार्यालय प्रथाओं और प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- निदेशक स्तर के अधिकारियों हेतु बजटिंग, वित्तीय प्रक्रियाओं एवं कार्मिक प्रबंधन पर जीएसआईटीआई में एक विशेष वार्षिक पाठ्यक्रम आयोजित किया जाए और यह कोर्स पूरा करने वाले निदेशकों को ही राज्य इकाइयों एवं क्षेत्रों में वित्त/प्रशासन में निदेशक/उप महानिदेशकों के पदों पर तैनात किया जाना चाहिए।
- तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों के समूह ग और घ कर्मचारियों हेतु क्षेत्रीय संस्थानों में कैप्सूल पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- जीएसआईटीआई स्वयं के लिए एवं क्षेत्रीय संस्थानों के लिए चरणबद्ध तरीके से मुद्रित एवं श्रव्य-दृश्य पाठ्यक्रम सामग्री का निर्माण करे। यह या तो प्राध्यापक वर्ग (उचित पारिश्रमिक प्रदत्त) के योगदान पर या शैक्षिक संस्थान को बाहर से प्राप्त के आधार पर हो सकता है।

12. उच्चाधिकार प्राप्त समिति की निम्न सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जीएसआई के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रशिक्षण परामर्शदात्री समिति, टीपीसीसी के समक्ष एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजना का निर्माण करेगी एवं प्रस्तुत करेगी :-

- जीएसआईटीआई में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण अभिवृत्ति के जीएसआई के सेवारत भूवैज्ञानिक होने चाहिए।
- जीएसआईटीआई में कुछ पद होने चाहिए, जिन पर केंद्रीय संस्थाओं और शैक्षिक संस्थाओं से भूवैज्ञानिकों को प्रतिनियुक्ति पर जीएसआई में कार्यभार ग्रहण करने में समर्थ बनाया जा सके।
- जीएसआईटीआई में एक ऐसी उदार नीति होनी चाहिए जिससे हवाई किराया, उचित मानदेय, आरामदायक आवास व्यवस्था इत्यादि जैसी उचित सुविधाएं प्रदान कर अतिथि प्राध्यापकों को आमंत्रित किया जा सके। जीएसआईटीआई को अतिथि प्राध्यापकों का एक डाटा बैंक बनाना चाहिए जिसे यह अपने सहायोगी संगठनों के साथ साझा कर सके, इससे संसाधनों के समूह में और वृद्धि होगी।
- जीएसआईटीआई को अपने आंतरिक प्रशिक्षण संसाधनों का विकास करने में सक्रिय रहना चाहिए। तदनुसार, जीएसआईटीआई यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षेत्रीय संस्थान स्तर पर अतिथि प्राध्यापकों और क्षेत्रीय घरेलू संसाधनों का उचित मिश्रण रहे।
- क्षेत्रीय संस्थानों में बहरहाल न्यूनतम कोर प्राध्यापक होंगे और निष्पादन मूल्यांकन की प्रणाली से क्षेत्रीय संस्थान स्थानीय अतिथि प्राध्यापकों के साथ-साथ जीएसआई के रिसोर्स व्यक्तियों को श्रेणी प्रदान कर उनके रिसोर्स क्षेत्रों की पहचान करे। जीएसआई के सेवानिवृत्त भूवैज्ञानिकों की क्रमबद्ध आधार पर पहचान की जानी चाहिए और सक्षमता वाले भूवैज्ञानिकों को उनके मूल संस्थान की निरंतर प्रगति में योगदान देने हेतु अभिप्रेरित किया जाना चाहिए।
- जीएसआईटीआई को अपने भूवैज्ञानिकों को विदेशी अनुभव दिलाने हेतु एक नीति का विकास करना चाहिए। जीएसआई का प्रयास होना चाहिए कि वह अपने जेटीएस/एसटीएस स्तर के कम से कम 30 प्रतिशत अधिकारियों को दो से चार सप्ताह के प्रशिक्षण अभिमुख कार्यक्रम हेतु विदेश भेजे। अधिकारियों का चयन उनके निष्पादन और अभिवृत्ति के आधार पर किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए जीएसआई प्रमुख संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक व्यवस्था कर सकती है।
- यह आवश्यक नहीं है कि वृहत अंतर्राष्ट्रीय कैन्वस के अनुभव की सुविधा केवल विदेशी दौरो से ही मिले। जीएसआईटीआई के अन्य भूवैज्ञानिक देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे कि उन भूवैज्ञानिकों, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजना संभव न हो, को लक्षित कर उनके लिए लगातार 'विजिट एंड ट्रेन' कार्यक्रम हो। ऐसे कार्यक्रमों में राज्य सरकारों को भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और ज्ञान को साझा करना जीएसआई की कोर गतिविधियों के भाग हैं। ये सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित होने चाहिए।

- जीएसआईटीआई डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिग्री स्तर के लिए पाठ्यक्रम सामग्री का विकास करेगा और एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा तय की गई अपेक्षाओं और सुविधाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को लगातार अद्यतन करेगा।

एस. विजय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

RESOLUTION

New Delhi, the 17th July, 2009

No. 27/79/2009-M-II/HPC.—The Government of India vide Resolution No. 11(39)/2007-M.I dated 7th January 2008 constituted a High Powered Committee (HPC) to review the functioning of the Geological Survey of India (GSI) and assess its capacity to meet the emerging challenges taking into account the organizations and technological and manpower resources.

2. The HPC in its Report submitted on 31st March 2009 made a large number of recommendations including on issues of training and capacity building and has stated that training services, particularly in the geosciences sector are crucial in the following contexts:

- Meeting the gap between academic knowledge and field practices, particularly of newly inducted geoscientists, to create efficiency.
- Knowledge enhancement by exposing practicing geoscientists to new developments in fields relating to their specialization, to create excellence.
- Knowledge pooling by enabling direct or indirect interaction amongst related fields, to create synergy.
- Human resource development related to attitudinal issues, cooperative behaviour, goal-orientation, quality consciousness, etc. to create *esprit-de-corps*.

3. The National Mineral Policy 2008 has also stressed on the need for a comprehensive institutional framework for R&D and Training as follows:

"To enable the use of state of the art exploration techniques, scientific mining and optimal use of minerals through ore dressing and beneficiation technologies it is necessary not only to promote research and development in minerals but to simultaneously establish appropriate educational and training facilities for human resources development to meet the manpower requirements of the mineral industry. The matters will receive prime importance and a comprehensive institutional framework for Research and Development, and Training will be developed"—(Para 2.7 of NMP 2008).

4. Presently the training needs of GSI, and other Institutions to some extent, are met by the Geological Survey of India Training Institute (GSITI) established in 1976. GSITI has its main training centre at Hyderabad with specialized divisions such as Photo Geology and Remote Sensing (PGRS), Geophysics, and the Centre for Geo-Information Management Training (CGMT). The Institute has six Field Training Centres, which are specialized in respect of the local geology. These Centres are operationalised only for the purpose of induction training of GSI's newly recruited geologists. There is a Training Advisory Committee headed by Director General, Geological Survey of India to coordinate training service planning.

5. The High Powered Committee had observed that the present structure of the Training Institute, while coping with the main task of providing high quality training to a limited number (about 50 in a year) and specialized training in a few disciplines for about 20-25 trainees at a time is clearly inadequate in view of the low capacity availability.

6. The HPC has recommended that training infrastructure needs a radical overhaul to meet the requirements arising out of the programmatic recommendations in its Report; and in particular:

- The Training infrastructure must be capable of imparting 9-12 months induction training for up to 300 new Geoscientists every year.
- The training infrastructure must also be capable of providing refresher or capsule courses for in-service geoscientists of GSI and State.
- There must be capacity available for high-end, cutting-edge knowledge delivery particularly for GSI and other Central Institutions.
- There must also be a capability for functioning as an internationally reputed training facility for private sector and geoscientists of other countries.

7. The HPC has recommended that the training must be taken up in Mission mode. GSITI at Hyderabad would house the Training Mission and would be responsible for over all Training Policy and coordination and programme goals. The GSITI may also be developed into a Centre of Excellence for providing high quality cutting-edge training/knowledge delivery, with state-of-the-art facilities. GSITI shall aspire to become a degree awarding institute by entering into suitable arrangement with universities at Hyderabad etc and accordingly develop a policy, and the Regional Institutes needs to develop the corresponding capability, of providing suitable training programmes on specific issues for M. Sc. and Ph. D. students. These would be supplemented by training programmes for specific field activities such as sample collection and ground-truthing and students opting for such training could then be deployed in groundwork for National Geochemical Mapping, Geomorphological Mapping or Hyperspectral Mapping fieldwork along with a Geoscientist. HPC has also made following recommendations:

- Regional Institutes be created at each Region for induction and in-service training of GSI and State DGMs. The Director (Training) located in the Regions but reporting to GSITI be declared head of the Regional Institute and conferred appropriate administrative and financial powers.
- The Regional Institutes would be part of the Regional Office premises and would function under the day-to-day control of the Regional HOD. The Director (Training) would be part of the Regional Office, but under functional change of GSITI for operationalising GSITI programmes in the Regional Institute.
- The Field Training Centres would function under the Regional Institute rather than GSITI in order to have better management control. Just as each FTC has a specialized function (dependent on the Regional geology) each Regional Training Institute must develop a range of specializations, based on its regional presence, and backed by well-equipped laboratories and specialized Geoscientists of the Region.

- The Training Advisory Committee headed by the Director General, GSI may from time to time recommend creation of additional Field Training Centres for specific subjects.
- The GSITI would conduct the Induction Course for GSI Geoscientists, International Courses, and Training of Trainers Courses for Regional Institutes and State Training Institutions and specialized courses, drawing on Regional Institute resources to the extent of the Regional specialization mentioned above.
- The Regional Institutes would conduct short-term courses (generally one week or less) for Regional GSI geoscientists, State Government geoscientists and courses on the regional specialization.
- The Annual Training Calendar for the Training Mission would be finalized by GSITI in its Training Advisory Committee for both its own programmes and Regional programmes factoring in State DGM requirements also, and placed in the CGPB for final approval.
- The Regional Institute Calendar will be prepared on the basis of SGPB inputs, regarding having needs of State geoscientists. Regional training need assessments and GSITI general directions. Each Regional Institute should run at least one course a year specially catering to State Government geoscientists of the Region, and courses on its regional specialization should be open to State Geoscientists so that they too can develop parallel capabilities to some extent, particularly on region specific issues.
- Each Regional Institute needs to develop linkages with Central and State Geoscientific Institutions and Universities located within the Region or having specialization related to the Region and offer training services tailored to their requirements. Similarly, the Regional Institute should endeavour to develop resource persons in such institutions to help run its training programmes. The Institutions who are part of CGPB and its Committees are the obvious first candidates in this respect.
- Regional Institutes may also provide training to technicians and geoscientists handling or utilizing technical and laboratory equipment, particularly newly acquired sophisticated equipment.

8. The HPC has also recommended that the 'Training Advisory Committee' presently headed by the Director General and comprising the heads of Regions and Wings needs to be energized in order to develop, implement and monitor the new approach to training services recommended by the Committee. In view of the fact that the training activity is being vastly expanded to cover all stakeholder organizations, the Committee recommends that in addition to the Training Advisory Committee, there should be a Training Policy Coordination Committee (TPCC) chaired by Secretary, Mines and the TPCC should be responsible for the overall policy and annual strategy.

9. The Government after careful consideration has accepted the recommendations of the High Powered Committee and hereby resolves that existing GSITI at Hyderabad shall house the Training Mission and the existing Field Training Centres (FTC) shall be attached with the Regions under whose jurisdiction they are

situated. The present Group C&D incumbents in the FTCs and the GSITI shall continue to be part of the existing centralized cadre for purposes of seniority and promotion for such period as may be necessary and GSITI shall be the cadre controlling authority for the purpose. All posts for the FTCs will be budgeted with the Regional Office to which they are attached, and the Regional Office shall be responsible for all operational and administrative matters relating to the FTCs.

10. The Government also hereby constitutes a Training Policy Coordination Committee (TPCC) as follows:-

▪ Secretary, Mines, Government of India	Chairman
▪ Additional Secretary/Joint Secretary, Mines	Member
▪ JS&FA, Mines	Member
▪ Director General, GSI	Member
▪ Addl. DG, GSI* [Support System-III] (Science Policy)	Member
▪ DDG, GSITI	Member Secretary
▪ Representatives of Dept. of S&T *	Member
▪ Ministry of Earth Science *	Member
▪ Representative of Ministry of HRD*	Member
▪ Representative of Ministry of DoPT*	Member
▪ Representative from AICTE*	Member
▪ Secretary, Mining & Geology of two State Governments (to be nominated each year).	

* Not below the status of Joint Secretary

* Designated as Training Manager

11. The TPCC may meet once a year to review training activities of Training Mission, approve policy and strategy initiatives. The TPCC shall generally work within the following framework:-

- The basic approach must be 'training for all'.
- There must be a training needs assessment and training requirements should be set out on that basis, covering short term and long-term in-house training as well as outsourced (i.e. outside GSITI) training.
- Training must cover both the geoscientific disciplines and administration/management areas, with weightage based on the target group.
- There must be a concept of periodical in-service training at various hierarchical levels in order to equip individuals to shoulder the expected higher responsibilities.
- The Training Mission may identify institution such as ASCI and IIMs and enter into long term MoUs for paid training programmes for its Middle and higher Managements.

- Induction Training for new inductees during probation period must be followed by a Departmental Examination, clearance of which must be a prerequisite for successful completion of probation.
- Support stream staff must be trained in the office practices and procedures relevant to their stream.
- A special annual course on Budgeting, financial procedures, administrative procedures and personnel management must be organized at GSITI for Director Level officers and only those Directors completing the course must be posted at Directors/DDGs in-charge of Finance/Administration at State Units and Regions.
- Capsule courses must be conducted at Regional Institute for Group C and Group D staff, both technical and non-technical.
- GSITI must systematically develop course material, printed as well as audio-visuals for itself and Regional Institutes. These could either be based on faculty contributions (suitably remunerated) or outsourced to academic institution.

12. The Training Advisory Committee under the Chairmanship of DG, GSI shall prepare and place before the TPCC a long-term perspective plan, keeping in view the following recommendations of the High Powered Committee:-

- GSITI should consist largely of in-service Geoscientists from GSI having training aptitude.
- GSITI must have some posts to enable geoscientists from Central Institutions and academia to join GSI on deputation.
- GSITI must have a very liberal policy for inviting guest faculty by providing adequate facilities including airfare, a substantial honorarium, comfortable stay facilities, etc. GSITI may create a data bank of guest faculty which it may share with sister organizations as this would further increase the pool of resources.
- GSITI must be proactive in developing its internal training resources. Accordingly, GSITI must ensure that at the Regional Institute Level, there is a fair mix of guest faculty and Regional in-house resources.
- Regional Institutes would have minimal core faculty in any case, and through a system of performance appraisal, the Regional Institutes must grade local guest faculty as well as GSI resource persons and identify their resource areas. Retired GSI Geoscientists must be identified on a systematic basis and those with capability must be motivated to contribute to the continued growth of their parent Institution.
- GSITI must develop a policy for foreign exposure of its Geoscientists. It should be the endeavour of GSI to send at least 30% of its officers at JTS/STS Level for a two to four week training oriented program abroad. The officers must be selected on the basis of their performance and aptitude and GSI may enter into long-term arrangements with premier institutions for the purpose.

- It is not necessary that exposure to the wider international canvas be facilitated only by visits abroad. GSITI must enter into bilateral arrangements with its counterparts in other geoscientific nations so that there is a continuous 'visit & train' programme aimed at those geoscientists who may not be able to be deputed abroad for training. In such programmes, State Governments too must be encouraged to participate.
- Training, capacity building and knowledge sharing is part of the core activity of GSI. These must be fully funded by the Government.
- GSITI to develop course content for Diploma and Post Graduate degree level and to continuously update course content in line with the requirements and facilities set out by AICTE/UGC.

S. VIJAY KUMAR, Addl. Secy.